

भारत के लिये जनसांख्यकीय संरचना का लाभ उठाने का अवसर

यह एडटोरियल 06/07/2023 को 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित "How India can leverage its biggest strength" लेख पर आधारित है। इसमें जनसांख्यकीय लाभांश से जुड़े अवसरों और चुनौतियों के बारे में चर्चा की गई है।

प्रलिमिस के लिये:

जन शक्तिपूर्वक संस्थान, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय प्रशाकिषुता संवरद्धन योजना, संकलि इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टारट-अप इंडिया, आयुषमान भारत, सब्वच्छ भारत मणिन, प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना, समग्र शक्ति कार्यक्रम, राष्ट्रीय शक्ति नीति 2020, बेरोजगारी, प्रजनन दर, मानव विकास सूचकांक

मेन्स के लिये:

भारत के जनसांख्यकीय लाभांश से जुड़ी चुनौतियाँ

भारत विश्व के सबसे अधिक आबादी वाले देशों में सबसे युवा है, जहाँ की औसत आयु 29 वर्ष है। भारत अपनी विशाल आबादी के साथ अभी एक ऐसे चरण में है जिसमें इसकी कार्यशील आयु आबादी की वृद्धि हो रही है और इसका वृद्धिवस्था नियन्त्रित अनुपात वर्ष 2075 में 37% तक पहुँच जाएगा। वृद्धि आबादी में वृद्धि के साथ वैश्वकि जनसांख्या वृद्धि होती जा रही है, जबकि प्रजनन दर में भारी कमी आई है। इससे भारत को अपनी अनुकूल जनसांख्यकीय संरचना का लाभ उठाने का एक अनूठा अवसर प्राप्त हो रहा है, जो इसकी आरथिक वृद्धि और सामाजिक विकास को बढ़ावा दे सकता है। हालाँकि, इस क्षमता को प्राप्त करने के लिये भारत को कुछ प्रमुख चुनौतियों को संबोधित करने और विभिन्न क्षेत्रों में कुछ रणनीतिक सुधारों को लागू करने की आवश्यकता है।

भारत के जनसांख्यकीय लाभांश के लिये कौन-से अवसर मौजूद हैं?

- उच्च आरथिक विकास:
 - एक विशाल और युवा कार्यशील आबादी शर्म आपूर्ति, उत्पादकता, बचत एवं नविश को बढ़ा सकती है, जिससे उच्च जीडीपी विकास और प्रति विद्युतीय कार्यक्रमों की स्थिति प्राप्त हो सकती है।
- वृहत् प्रतिस्परद्धात्मकता:
 - एक कुशल कार्यबल वैश्वकि बाज़ार में, विशेष रूप से विनिर्माण, सेवाओं और कृषि जैसे शर्म-गहन क्षेत्रों में भारत की प्रतिस्परद्धात्मकता को बढ़ा सकता है।
 - भारत विकासित देशों के वृद्धि कार्यशील बाज़ारों (ageing markets) में अपने नियात की बढ़ती मांग से भी लाभान्वति हो सकता है।
- सामाजिक विकास:
 - यह स्वास्थ्य, शक्ति, लैंगिक समानता और सामाजिक संसंजन में सुधार लाकर सामाजिक विकास में योगदान दे सकता है।
 - एक सशक्त आबादी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और नागरिक सहभागिता में भी अधिक सक्रिय रूप से भागीदारी कर सकती है।
- नवाचार और उद्यमता:
 - एक रचनात्मक आबादी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कला एवं संस्कृति जैसे विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और उद्यमता को बढ़ावा दे सकती है।
 - एक आकांक्षी आबादी आरथिक विविधीकरण के लिये नए बाज़ारों और अवसरों का सृजन भी कर सकती है।

जनसांख्यकीय लाभांश प्राप्त करने की राह की प्रमुख चुनौतियाँ

- बेरोजगारी और रोजगारहीन विकास:
 - उपयुक्त नीतियों के बनाना, कार्यशील आयु आबादी में वृद्धि से बेरोजगारी बढ़ा सकती है, जिससे आरथिक और सामाजिक संकट बढ़ा सकते हैं।
 - भारत में रोजगारहीन विकास व्यापक रूप से मौजूद है, जहाँ मौजूदा कार्यशील आयु आबादी का भी पूरी तरह समावेश नहीं हो पाता है।
 - 'सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी' (CIME) के अनुसार जनवरी 2023 में भारत की बेरोजगारी दर 7.1 प्रतिशत के स्तर पर थी।
- महाला शर्म बल भागीदारी में गरिवट:
 - सामाजिक-सांस्कृतिक कारक और बढ़ती पारिवारिक आय भारत की महाला शर्म बल भागीदारी (FLFP) में गरिवट के प्रमुख कारण रहे

हैं।

- योग्यता-प्राप्त महलियों का एक बड़ा भाग स्थानीय क्षेत्र में (वशिष्ठ रूप से गरामीण इलाकों में) उपयुक्त रोज़गार अवसर न होने से लेकर पारवारिकि उत्तरदायतिवों और विवाह जैसे वभिन्न कारणों से कारबल से बाहर हो जाता है।
- भारत की FLFP दर वैश्विकी औसत से नीचे है।
 - CMIE के आँकड़ों के अनुसार, भारत में जहाँ पुरुष श्रम बल भागीदारी दर 67.4% थी, वही महलिया श्रम बल भागीदारी दर 9.4% तक नमिन थी (दिसंबर 2021 तक की स्थिति)।

■ कौशल और मानव विकास की कमी:

- वर्तमान समय में बढ़ते नए क्षेत्रों और अवसरों के कारण 'सकलिंगि' और 'रीसकलिंगि' महत्वपूर्ण है।
- नमिन मानव पूंजी आधार और कम कुशल श्रम बल के कारण भारत अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम नहीं भी हो सकता है।
- **एसोचैम (ASSOCHAM)** के अनुसार, केवल 20-30% इंजीनियरों को ही उनके कौशल के अनुकूल नौकरी मिल पाती है। इस प्रकार, नमिन मानव पूंजी आधार और कौशल की कमी एक बड़ी चुनौती है।
- UNDP के **मानव विकास सूचकांक (HDI)** (2021-22) में भारत 191 देशों की सूची में 132वें स्थान पर था, जो चतिंजनक है।
 - HDI मानव विकास के तीन बुनियादी आयामों में औसत उपलब्धियों की माप करता है। ये तीन आयाम हैं-सुदृढ़ एवं स्वस्थ जीवन, ज्ञान तक पहुँच और एक सभ्य जीवन स्तर।

भारत अपने जनसांख्यकीय लाभांश में कैसे सुधार कर सकता है?

■ कौशल और रोज़गार सृजन:

- भारत के पास लगभग 500 मिलियन लोगों का विशाल श्रम बल मौजूद है, जिसके आने वाले वर्षों में और बढ़ने की उम्मीद है।
- हालाँकि, उनमें से अधिकांश या तो अकुशल हैं या अल्प-कुशल हैं और बदलते बाज़ार परदिश्य में नमिन उत्पादकता और रोज़गार योग्यता रखते हैं।

■ LFPR में सुधार करना:

- भारत को श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) में सुधार करने की ज़रूरत है, जो वर्तमान में लगभग 50 प्रतशित है। इसके लिये प्रत्येक वर्ष रोज़गार बाज़ार में प्रवेश करने वाले युवाओं के लिये अधिकाधिक रोज़गार अवसरों का सृजन करना होगा।
- इसके लिये नमिन उत्पादकता वाले कृषी क्षेत्र से उच्च उत्पादकता वाले वनिरिमाण एवं सेवा क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ने की आवश्यकता है, जो अधिक श्रम को अवशोषित कर सकते हैं और अधिक आय उत्पन्न कर सकते हैं।

■ कौशल विकास कार्यक्रमों में सुधार लाना:

- भारत द्वारा अपने कौशल विकास कार्यक्रमों की गुणवत्ता एवं प्रासंगिकता बढ़ाने की भी आवश्यकता है, जिनका उद्देश्य वभिन्न क्षेत्रों में लाखों श्रमकों को प्रशिक्षित और प्रमाणीकृत करना है।
- इन कार्यक्रमों को उद्योग की मांग, वैश्विक मानकों और उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ संरेख्यता करिया जाना चाहयि तथा श्रमकों के लिये आजीवन अधिगम (लर्निंग) के अवसर प्रदान करने चाहयि।
- हालाँकि, इनके द्वायरे को बढ़ाने और इन्हें बेहतर बनाने की ज़रूरत है ताकि और श्रमकों तक (वशिष्ठ रूप से **अनौपचारिक क्षेत्र** के श्रमकों तक) पहुँच बन सके।

■ वज़िन 2025:

- कौशल मशिन में कौशल विकास एवं उद्यमता मंत्रालय (MSDE) का वज़िन 2025 शामिल है जो शक्ति एवं कौशल के बीच संबंधों में सुधार लाने, औपचारिक कौशल के लिये मांग को उत्प्रेरणा करने और एक उच्च-कुशल पारितित्र का सृजन करने पर लक्षित है।

■ स्वास्थ्य और कल्याण:

- भारत ने पछिले कुछ वर्षों में जीवन प्रत्याशा, शशि मृत्यु दर और मातृ मृत्यु अनुपात जैसे अपने स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार लाने में उल्लेखनीय प्रगतिकी है।
 - हालाँकि, अपनी विशाल एवं विविध आबादी के लिये स्वास्थ्य समानता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने में इसे अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
 - भारत पर संचारी और गैर-संचारी रोगों का भारी बोझ है, जो इसके कारबल के स्वास्थ्य और उत्पादकता को प्रभावित करते हैं।
 - भारत सभी को प्रायाप्त और सास्ती स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान कर सकने के लिये स्वास्थ्य अवसंरचना, मानव संसाधन और वित्तीय संसाधन की कमी भी रखता है।

○ सार्वजनिक स्वास्थ्य परणाली में नविश:

- भारत को अपनी सार्वजनिक स्वास्थ्य परणाली में और अधिक नविश करने की आवश्यकता है, जो इसकी लगभग 70 प्रतशित आबादी की सेवा करती है। इसे अपने प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल नेटवर्क को भी सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, जो अधिकांश लोगों के लिये संपर्क का पहला बुद्धि होता है।

○ दवाओं की वहनीयता सुनिश्चित करना:

- भारत 50 बलियन अमेरिकी डॉलर के उद्योग के साथ दवाओं और टीकों के मामले में विश्व का अग्रणी देश है। विश्व में DPT, BCG और खसरे के टीकों में लगभग 60 प्रतशित हसिसेदारी भारत की है।
- हालाँकि, यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि दवाएँ और टीके समाज के सभी वर्गों के लिये सुलभ और वहनीय हों।

■ शक्ति और नवाचार:

- भारत में युवा और प्रत्याशाली लोगों का एक बड़ा समूह मौजूद है, जो इसकी आरथकि वृद्धि और सामाजिक विकास में योगदान दे सकता है।
- हालाँकि, इसके बच्चों और युवाओं में नरिक्षणता, स्कूल डरॉप आउट और लर्निंग की कमी की दर भी उच्च है, जो उनकी क्षमता और आकांक्षाओं को प्रभावित करती है।

○ शक्ति तक सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना:

- भारत को परी-पराइमरी से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक स्कूली शक्ति के सभी स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण शक्ति की

सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चिति करने की आवश्यकता है।

- इसे पाठ्यक्रम, शिक्षाशास्त्र, मूल्यांकन और शिक्षक प्रशिक्षण प्रणालियों को संवृद्ध कर अपने छात्रों के अधिगम प्रतिफिलों में सुधार लाने की भी आवश्यकता है।
- इसके साथ ही लगि, जाति, क्षेत्र और सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर शिक्षा में व्याप्त असमानताओं को भी कम करने की आवश्यकता है।

प्रमुख सरकारी पहलें

■ कौशल उन्नयन और उद्यमता के लिये:

- [जन शिक्षण संस्थान](#)
- [प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना](#)
- [राष्ट्रीय प्रशिक्षण संवरद्धन योजना](#)
- [सकल इंडिया](#)
- [मेक इन इंडिया](#)
- [स्टारट-अप इंडिया](#)

■ स्वास्थ्य और कल्याण के लिये:

- [आयुषमान भारत](#)
- [स्वच्छ भारत मिशन](#)
- [प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना](#)

■ शिक्षा और नवाचार के लिये:

- [समग्र शिक्षा कार्यक्रम](#)
- [राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020](#)

आगे की राह

■ क्षमता दृष्टिकोण का अनुसरण करना:

- मानव कल्याण और विकास की बहुआयामी प्रकृति को चिह्निति करें और प्रतिव्यक्ति स्कल घरेलू उत्पाद या हेड काउंट अनुपात जैसे संकीरण संकेतकों से आगे बढ़ें।
- भारत में विभिन्न समूहों और क्षेत्रों की क्षमताओं में अंतराल एवं असमानताओं की पहचान करें और लक्षित हस्तक्षेपों एवं सशक्तिकरण रणनीतियों के माध्यम से उन्हें संबोधिति करें।
- स्वयं के जीवन को आकार देने और उन पर असर करने वाले नियन्यों को प्रभाविति करने में लोगों की, विशेष रूप से समाज के हाशमि पर स्थिति और कमज़ोर वर्गों की एजेंसी और भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए।
- विकास नीतियों और अभ्यासों के लिये मार्गदर्शक सदिधांतों के रूप में सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकारों को बढ़ावा देना तथा शासन में जवाबदेही एवं पारदर्शिता सुनिश्चिति करना।
- नवाचार और रचनात्मकता की संस्कृति को बढ़ावा देना जो सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के लिये भारत की युवा आबादी की प्रतिभा एवं आकांक्षाओं का लाभ उठा सके।

■ वनिरिमाण गतिविधियों में तेज़ी लाना:

- लाखों नौकरियों का सृजन करने और नियात को बढ़ावा देने हेतु वनिरिमाण क्षेत्र की क्षमता का दोहन करने की ज़रूरत है।
- वनिरिमाण विशाल और युवा शर्म बल, विशेषकर नमिन या मध्यम कौशल वाले लोगों के लिये रोज़गार के अवसर प्रदान कर सकता है।
- वनिरिमाण वैश्वकि बाज़ार में भारत की प्रतिस्परद्धात्मकता को बढ़ा सकता है, इसकी नियात टोकरी में विधिता ला सकता है और इसके व्यापार घाटे को कम कर सकता है।
- वनिरिमाण अर्थव्यवस्था में नवाचार और प्रौद्योगिकी उन्नयन को भी प्रेरिति कर सकता है।

■ कारोबारी माहौल को बढ़ावा देना:

- भारत को वनिरिमाण में अधिक घरेलू और विदेशी निवेश आकर्षिति करने के लिये अपनेकारोबारी माहौल, अवसंरचना, लॉजिस्टिक्स एवं व्यापार सुविधा में सुधार लाने की ज़रूरत है।

■ शर्म-गहन क्षेत्रों को बढ़ावा देना:

- भारत को वस्त्र, परधिन, चर्म, जूते, खिलौने और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे शर्म-गहन क्षेत्रों को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जिनमें उच्च रोज़गार लोग और नियात क्षमता है।
- भारत को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) को भी समर्थन देने की ज़रूरत है, जो वनिरिमाण क्षेत्र की रीढ़ हैं। यह समर्थन ऋण, प्रौद्योगिकी, बाज़ार एवं कौशल तक पहुँच प्रदान करने के रूप में दिया जा सकता है।

■ डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना:

- डिजिटल प्रौद्योगिकियों अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विकास, नवाचार और समावेशन के नए अवसर प्रदान कर सकती हैं।
- डिजिटल प्रौद्योगिकियों लाखों लोगों के लिये, विशेष रूप से दूरदराज के या कम सेवा वाले क्षेत्रों के लोगों के लिये व्यापार, सेवा, बाज़ार और वित्त तक पहुँच को सक्षम कर सकती हैं।
- डिजिटल प्रौद्योगिकियों शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, खुदरा और ई-कॉमर्स जैसे विभिन्न क्षेत्रों में दक्षता, पारदर्शिता,

जवाबदेही एवं गुणवत्ता की भी वृद्धकिर सकती है।

अभ्यास प्रश्न: युवा आबादी के माध्यम से भारत की क्षमता को उजागर करने में विद्यमान चुनौतियों और समाधानों की चर्चा कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQs)

प्रश्न:

प्रश्न. भारत को "जनसंख्यकीय लाभांश" वाला देश माना जाता है। यह क्सि कारण है? (2011)

- (a) 15 वर्ष से कम आयु वर्ग में इसकी उच्च जनसंख्या
- (b) 15-64 वर्ष के आयु वर्ग में इसकी उच्च जनसंख्या
- (c) 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में इसकी उच्च जनसंख्या
- (d) इसकी उच्च कुल जनसंख्या

उत्तर: (b)

प्रश्न:

प्रश्न. 1 जनसंख्या शाक्षा के प्रमुख उद्देश्यों की विचना कीजिये तथा भारत में उन्हें प्राप्त करने के उपायों का वस्तार से उल्लेख कीजिये। (2021)

प्रश्न. 2 "महिलाओं को सशक्त बनाना जनसंख्या वृद्धिको नयितरति करने की कुंजी है।" चर्चा कीजिये। (2019)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/current-affairs-news-analysis-editorials/news-editorials/08-07-2023/print>